शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक-48 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 04-11 दिसम्बर 2023 मूल्य पांच रूपये

सोलन की हार वर्ष की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना है

लोस चुनावों से पूर्व सरकार को अपनी कार्यशैली की समीक्षा करनी होगी

कठिन वितीय स्थितियों में राजनीतिक बोझ बढ़ाना नुकसानदेह होगा

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार का सत्ता में एक वर्ष पूरा हो गया है। इस अवसर पर सरकार धर्मशाला में एक राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन करने जा रही है। इस आयोजन में यह स्वभाविक है कि सरकार इसमें अपनी एक वर्ष की उपलब्धियां और भविष्य की योजनाओं का प्रारूप जनता के सामने रखेगी। जनता सरकार से कितना संतुष्ट है इसका प्रमाण तो आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम ही होंगे यह तय है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों के लिये इस दौरान जो कुछ घटा है इसका व्यवहारिक आकलन करना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि चुनावी फ्रंट पर सबसे बड़ी घटना सोलन नगर निगम के महापौर और उप महापौर पदों का चुनाव है। इस निगम में पार्षदों का बहुमत कांग्रेस का है यानि जनता ने चुनाव में कांग्रेस पर भरोसा किया था। लेकिन अब जनता के इस भरोसे को कांग्रेस के ही पार्षदों ने संतुष्ट और असंतुष्ट खेमे में बांटकर तोड़ दिया है। पार्षदों की यह खेमेबाजी बड़े अरसे से चर्चा में थी और तब खुलकर सामने आ गयी थी जब कांग्रेस के ही पार्षद भाजपा के साथ मिलकर अविश्वास प्रस्ताव लाये थे। उस समय यदि इसका गंभीर संज्ञान ले लिया जाता तो शायद अब हार का मुख न देखना पड़ता। सोलन जिला से दो मुख्य संसदीय सचिव हैं जबकि सोलन के विधायक मंत्री हैं। इस चुनाव में सहमति बनाने के लिये दो और मंत्रियों की जिम्मेदारी भी लगाई गयी थी लेकिन सबके प्रयास असफल रहे। पार्षद पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता माने जाते हैं यदि ऐसे लोगों ने पार्टी के फैसले पर नाराजगी जताते हुए इस तरह का आचरण किया है तो इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिये। कहीं सरकार और संगठन में पूरे प्रदेश में ही ऐसी स्थिति तो नहीं बनती जा रही है। लोकसभा चुनावों से पूर्व सोलन की यह हार बहुत कुछ इंगित करती है क्योंकि हर कार्यकर्ता भी नेताओं पर नजर रख रहा है।

राजनीतिक फलक से हटकर यदि वित्तीय मुहाने की बात की जाये तो सरकार ने सत्ता संभालते ही प्रदेश के हालात श्रीलंका जैसे होने की चेतावनी दी थी। पूर्व सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया था। इस आश्य का श्वेत पत्र भी जनता के सामने रखा। लेकिन यह श्वेत पत्र जानकारी से आगे नहीं बढ़ा। लेकिन कठिन वित्तीय स्थिति के परिदृश्य में सरकार को जो लगाम अपने खर्चो पर लगानी चाहिये थी वह नहीं लग सकी। मुख्य संसदीय सचिवों से लेकर जो दूसरी राजनीतिक नियुक्तियां की गयी हैं उनका औचित्य जनता के सामने भ्रामकता से अधिक कुछ नहीं बन पाया है। अब सचेतक और उप सचेतक के पदों को भरने की चर्चा शुरू हो गयी है जबकि यह मामला भी प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित है। इसका फैसला आये बिना इन पदों को भरना फिर विवाद का विषय बनेगा। इसी तरह प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की बहाली भी आम आदमी में अनुचित मानी जा रही है। किसी भी कर्मचारी संगठन ने इसकी मांग नहीं की है। फिर प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में सरकार के फैसलों को ही तो कर्मचारी चुनौती देते हैं। यदि सरकार फैसला ही गलत न करें और उनको अपने ही स्तर पर सुलझा ले तो फिर ट्रिब्यूनल में जाने की नौबत ही नहीं आयेगी। ऐसे में आज ट्रिब्यूनल की बहाली को कुछ सेवानिवृत लोगों को रोजगार देने से अधिक नहीं देखा जा रहा है।

इस समय प्रदेश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। सरकार ने सौ दिन पूरे होने पर भी सरकारी क्षेत्र में तीस हजार और प्राइवेट क्षेत्र में 90,000 रोजगार देने का वायदा किया था। इसी सरकार की अपनी ही रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में सरकारी विभागों में 70,000 पद खाली हैं। अकेले शिक्षा विभाग में ही 22,000 पद खाली हैं और सरकार अगले सत्र से अंग्रेजी माध्यम में सरकारी स्कूलों में शिक्षण देने और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा कर रही है। क्या विभाग में इतने पद खाली होते हुए ऐसे कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक अन्जाम दिया जा सकेगा है इस पर सबकी निगाहें लगी हुई है। युवाओं को रोजगार देने के लिये ई-टैक्सी परमिट और सोलर पॉवर परियोजनाओं की शुरुआत एक अच्छा और सराहनीय फैसला माना जा रहा है। लेकिन लोस चुनावों से पहले यह कितनी व्यवहारिक शक्ल ले पाता है इस पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं। एक वर्ष में जितने आरोप विभिन्न पत्रों के माध्यम से प्रशासन पर लगे हैं उनकी चर्चा आने वाले चुनावों में विपक्ष अवश्य उठायेगा इसका जवाब सरकार कैसे देगी इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। सरकार और संगठन में तालमेल कैसे बैठ पाता है यह भी बड़ा मुद्दा रहेगा। क्योंकि तालमेल का अभाव पहले ही चर्चा में आ चुका है। ऐसे में एक वर्ष के आकलन में सरकार की कारगुजारी औसत से अधिक नहीं आंकी जा सकती। यह सही है कि आपदा ने सरकार के गणित को बुरी तरह प्रभावित किया है लेकिन इस आपदा से पहले ही सरकार ने अपना भार इतना बढ़ा लिया जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी। इसी भार के कारण सरकार का क्षेत्रिय सन्तुलन गड़बड़ाया है।

26वाँ डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्मृति व्याख्यान आयोजित

शिमला/शैल। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला द्वारा 7 दिसंबर 2023 को इण्डिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली के सभागार में 26वाँ डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्मृति

व्याख्यान आयोजित किया गया। यह व्याख्यान भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे द्वारा भारत की सौम्य शक्ति कौशलता – चुनौतियाँ एवं उत्तरदायित्व विषय पर प्रस्तुत किया गया।

संस्थान की अध्यक्ष प्रोफ़ेसर शशिप्रभा कुमार ने कहा कि यह स्मृति व्याख्यामाला वर्ष 1991 में आरंभ हुई थी और अभी तक जस्टिस लीला सेठ, कपिल वात्स्यान, प्रोफेसर डीपी चटोपध्याय, 14वें परम पावन दलाई लामा, जस्टिस पी. नरसिम्हा जैसे अनेक प्रतिष्ठित विद्वान विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दे चुके हैं जिनमें डॉ. विनय सहस्रबुद्धे द्वारा भारत की मृदु शक्ति कौशलता – चुनौतियाँ एवं उत्तरदायित्व विषय पर प्रस्तुत 26वां व्याख्यान विशेष महत्व रखता है।

डॉ. विनय सहस्रबुद्धे ने अपने व्याख्यान में कहा कि सौम्य शक्ति अपेक्षाकृत नव अवधारणा है। आज हम विश्व स्तर पर होने वाले विमर्शों का उल्लेख करते हैं कि क्योंकि उन्हें बड़े पैमाने पर जनमत की शक्ति के रूप में देखा जाता है। ऐसे विमर्शों, आख्यानों की तरह, सौम्य शक्ति भी एक ऐसा कारक है जो लोकप्रिय सोच को आकार देने के साथ-साथ उसे प्रतिबिंबित भी करता है। भारत को बाहरी दुनिया में इंडिया के नाम तो अभी जाना जाने लगा मगर भारतीय संस्कृति का प्रभाव सदियों पहले ही विश्व में फैल चुका था। प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार और दार्शनिक विल डयूरेंट जैसे कई विद्वानों ने ज्ञान के कई क्षेत्रों के उद्भव के स्थान के रूप में भारत के प्रभाव को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है।

उन्होंने कहा कि 'नित्यनूतन चिरपुरातन' की विशेषता भारतीय संस्कृति को कई मायनों में अद्वितीय बनाती है। साथ उन्होंने भारत के विश्व-दृष्टिकोण के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, हमारी विविधता में निहित एकता ने हमें न केवल समायोजित करने में बल्कि हमारी व्यापक विविधता के भी सक्षम बनाया है। प्राचीन भारतीय ज्ञान पद्धतियाँ महत्वपूर्ण हैं मगर दर्शन, चिकित्सा, गणित आदि में इतना गहन ज्ञान निहित होते हुए भी इन्हें अक्सर कम महत्व दिया जाता है या गलत समझा जाता है। उन्होंने कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य में सौम्य शक्ति बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बदलते वैश्विक परिवेश में इसके महत्व प्रमुखता से समझना चाहिए और इस मार्ग में आने वाली चुनौतियों का एकजुट होकर सामना करना चाहिए।

बता दें कि डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने वर्ष 1965 में शिमला स्थित अपने आवास राष्ट्रपति निवास में उच्च शोधकार्यो के लिए भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की स्थापना की थी। यह स्मृति व्याख्यान उस महान दार्शनिक राष्ट्रपति के प्रति शृंद्धाजलि स्वरूप हर वर्ष आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर संस्थान द्वारा हिन्दी माध्यम से प्रकाशित दो अर्द्धवार्षिक शोध पत्रिकाओं हिमांजलि अंक – 27 तथा चेतना अंक – 5 का भी लोकार्पण किया गया। चेतना पत्रिका के इस अंक का संपादन हिन्दी के जाने माने विद्वान एवं संस्थान के पूर्व अध्येता प्रोफेसर माधव हाड़ा ने किया है जबकि चेतना पत्रिका के कार्यकारी संपादक संस्थान में अध्ययनरत अध्येता प्रोफेसर राजेन्द्र बड़गूज़र हैं।

2047 तक विकसित भारत-युवाओं की आवाज विषय पर कार्यशाला आयोजित

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में '2047 तक विकसित भारत – वायस ऑफ यूथ' विषय पर आयोजित कार्यशाला को दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि भारत विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हमें अगले 25 वर्षों में एक विकसित भारत बनाने के लिए युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा में लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित राष्ट्र में हमारे योगदान को लेकर प्रधानमंत्री

नरेन्द्र मोदी का दृष्टिकोण और आमंत्रित विचार अधिक महत्वपूर्ण हैं।

राज्यपाल ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक विजन डाक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। इसका मसौदा उन संस्थागत और संरचनात्मक परिवर्तनों और सुधारों की रूपरेखा तैयार करेगा जिनकी देश को एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए आवश्यकता होगी।

शुक्ल ने कहा कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। 144 करोड़ की आबादी के साथ, भारत 29 वर्ष की औसत आयु वाले सबसे युवा देशों में से एक है। यह विश्व की कुल युवा जनसंख्या का लगभग 20 प्रतिशत था। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत बड़ा अवसर है, जिसके 2047 तक बने रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस जनसांख्यिकीय लाभांश का सदुपयोग करके हम भारत को विकसित भारत के रूप में आगे ले जा सकते हैं।

उन्होंने विकसित भारत के अभियान को विश्वविद्यालय स्तर पर संचालित करने और युवाओं के सुझाव आमंत्रित कर उन्हें दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने को कहा।

इससे पहले प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया – 2047 आइडिया पोर्टल के लॉन्चिंग कार्यक्रम और उनके वर्चुअल संबोधन का भी यहां प्रसारण किया गया।

राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा ने यहां नीति आयोग द्वारा निर्धारित विषयवस्तु पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

कार्यशाला में पांच समूह बनाये गये, जिन्होंने इस अवसर पर सशक्त भारतीय, संपन्न एवं सतत अर्थव्यवस्था, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सुशासन एवं सुरक्षा तथा विश्व में भारत विषय पर अपनी प्रस्तुति दी। कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, निदेशक, प्रति-कुलपति, डीन, प्राचार्य, प्रोफेसर और संकाय सदस्यों ने भाग लिया।

पूर्वांचल की समृद्ध संस्कृति और विरासत को संजो कर रखने का आहवान:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने पूर्वांचल के लोगों से आने वाली पीढ़ियों के लिए पूर्वांचल की

समृद्ध संस्कृति को संरक्षित करने के लिए यहां परंपराओं और विरासत को संजो कर रखने का आहवान किया। यह बात उन्होंने नई दिल्ली में माटी ट्रस्ट द्वारा आयोजित 7वें माटी सम्मान समारोह को सम्बोधित करते हुए कही।

यह कार्यक्रम पूर्वांचल की कला और समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया था।

राज्यपाल ने पूर्वांचल की संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाले समृद्ध लोक गीतों को संरक्षित करने के महत्व पर प्रकाश डाला और आने वाली पीढ़ियों के लिए पौराणिक परंपराओं के साथ एक मजबूत संबंध स्थापित करने में इन लोकगीतों की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हालांकि देशभर में भाषा, खान-पान, रीति-रिवाज और परंपराएं अलग-अलग हैं, लेकिन पूर्वांचल की भावना देशभर में रहने वाले सभी पूर्वांचलियों को एकजुट करती है। राज्यपाल ने सनातन संस्कृति के महत्व पर भी बल दिया तथा वर्तमान व भावी पीढ़ियों से इस सम्बंध में जागरूक होने और गर्व करने का आहवान किया। उन्होंने पवित्र शहर काशी और देश भर के घरों में पाई जाने वाली रामायण जैसी पवित्र पुस्तकों के प्रकाशन के लिए प्रसिद्ध गोरखपुर के गीता प्रेस जैसे स्थलों के बारे में भी बताया।

राज्यपाल ने स्वतंत्रता संग्राम में क्षेत्र के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और स्वतंत्रता संग्राम में इस धरती के नायकों की भूमिका व अन्याय के खिलाफ इनके संघर्ष की सराहना की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने लोक गायिका मालिनी अवस्थी, डॉ.एनएल खन्ना, रवि दुबे, रजनीकांत राय, चन्द्रशेखर सिंह, एन.के. यादव सहित अपने-अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली पूर्वांचल की लोकप्रिय हस्तियों को सम्मानित किया।

माटी ट्रस्ट के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने ट्रस्ट के लक्ष्यों और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला।

मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ

शिमला/शैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव एम.सुधा देवी ने मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय चिकित्सा स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान तथा महिला एवं बाल विकास निदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

का शुभारम्भ किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 67 बाल संरक्षण इकाईयों एवं बाल देखभाल संस्थाओं के कर्मचारी भाग ले रहे हैं।

एम.सुधा देवी ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को बच्चों के बचपन और उनके भावनात्मक एवं संवेदनशील अनुभवों के बारे में जागरूक करना है। साथ ही उनमें बाल अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोणों की समझ विकसित करने तथा यह समझने में सक्षम बनाना है कि बच्चे अपने अनुभव कैसे समझते हैं। उन्होंने ज़िलों से आये बाल संरक्षण इकाईयों के प्रतिभागियों को बच्चों के सर्वोत्तम हित, बच्चों के समग्र विकास, उनकी सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास की जरूरतों को सुनिश्चित करने के दृष्टिगत कार्य योजना तैयार करने के लिए भी प्रेरित किया।

महिला एवं बाल विकास निदेशक रूपाली ठाकुर ने प्रतिभागियों से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान बच्चों की मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और व्यवहार सम्बंधी समस्याओं पर समझ बढ़ाने का आहवान किया। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम से सम्बंधित विस्तृत रूपरेखा भी प्रस्तुत की।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान की तकनीकी और परिचालन प्रमुख शीला रामास्वामी तथा कांगड़ा क्षेत्र के लिए संवाद परियोजना प्रबंधक कृति टिक्कु बतौर प्रवक्ता इसमें शामिल हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर, कांगड़ा, हमीरपुर, चम्बा और ऊना के अंतर्गत आने वाली इकाईयों और संस्थानों के कर्मचारी भाग ले रहे हैं।

सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान देने का आह्वान किया:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों के सभी सदस्यों और उनके परिवारों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर मदन शील शर्मा (सेवानिवृत्त) ने राज्यपाल के कोट पर सशस्त्र सेना ध्वज लगाया।

इस अवसर पर, राज्यपाल ने सभी नागरिकों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में उदारतापूर्वक योगदान देने और सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के दृष्टिगत इस पुनीत कार्य में सहयोग करने की आहवान किया। उन्होंने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। देश सेवा करते हुए सेना, नौसेना और वायु सेना के जवानों द्वारा दिया गया अतुलनीय बलिदान हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

दो माह में तैयार होगी पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत प्रदेश सरकार हरित ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए सतत् विकास की अवधारणा को साकार कर रही है। ऊना जिला के पेखूबेला में प्रदेश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना इसी दिशा में एक सार्थक कदम है। इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना को दो माह में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

हिमाचल को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए 59 हेक्टेयर में स्थापित होने वाली इस परियोजना में 82,656 सौर माडयूल स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 दिसंबर, 2023 को इस 32 मेगावाट की इस सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी और फरवरी, 2024 के पहले सप्ताह तक इसे पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में यह परियोजना सहायक सिद्ध होगी। इस परियोजना के स्थापित होने से राज्य की विद्युत आवश्यकतों की पूर्ति होने के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन में भी उल्लेखनीय कमी आएगी।

पेखुबेला सौर परियोजना का कार्य 19 मई, 2023 को अवार्ड किया गया था। इससे वार्षिक 66.10 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया जाएगा। यहां पर उत्पादित बिजली 1.88 किलोमीटर लम्बी रक्कड़-टाहलीवाल 132 केवी डबल सर्किट लाइन के माध्यम से पारेषित की जाएगी। इसके लिए लाइन-इन, लाइन-आउट तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड राज्य में आगामी दो वर्षों में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य के साथ कार्य कर रहा है। सरकार द्वारा 200 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही अतिरिक्त 40 मेगावाट के लिए निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके अलावा 100 मेगावाट की अन्य सौर ऊर्जा परियोजनाएं प्रारंभिक चरण में हैं।

वर्तमान में जल-विद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं में एचपीपीसीएल की कुल क्षमता 3,275 मेगावाट है। 281 मेगावाट क्षमता की चार परियोजनाएं पूर्ण होने के चरण में है जबकि कुल 690 मेगावाट की अतिरिक्त पांच परियोजनाएं वर्तमान में निर्माणाधीन हैं। 272 मेगावाट की चार परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त 926 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली दस परियोजनाओं के लिए अन्वेषण कार्य जारी है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के दूसरे चरण में प्रदेश सरकार हरित ऊर्जा को रोजगार सृजन के साथ जोड़ेगी। इसके तहत राज्य के युवाओं को 100 किलोवाट से एक मेगावाट क्षमता तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह नवोन्मेषी पहल न केवल हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्वरोजगार स्थापित करने की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण योगदान देगी।

मुख्यमंत्री ने रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनने पर दी बधाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रेवंत रेड्डी को हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर बधाई दी है। रेवंत रेड्डी और मंत्रिमण्डल के शपथ ग्रहण समारोह में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हुए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आशा व्यक्त की कि नवगठित कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में तेलंगाना राज्य तेजी से प्रगति करेगा और हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयां हासिल करेगा।

उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जनता ने रेड्डी के नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है और नवगठित तेलंगाना सरकार जनता की आशाओं पर खरी उतरेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ विधायक सुरेश कुमार भी उपस्थित रहे।

ई-टैक्सी खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करेगी प्रदेश सरकार:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैंकों से सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं के लिए उदारतापूर्वक व रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है, ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

मुख्यमंत्री सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र तथा निजी बैंकों के प्रतिनिधियों की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने 680 करोड़ रूपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के प्रथम चरण की शुरूआत की है। इसके तहत ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि ई-टैक्सियों को सरकारी कार्यालयों में भी लगाया जाएगा ताकि युवाओं को एक निश्चित आय का साधन भी उपलब्ध हो सके।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस योजना के तहत बैंक युवाओं को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि उन पर ई.एम.आई. का बोझ कम हो सके। उन्होंने कहा कि इस ऋण के लिए गारंटी सरकार देगी। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में पंचायत स्तर पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जाएंगे। उन्होंने सभी बैंकों को ब्याज की दरें राज्य सरकार को शीघ्र भेजने को भी कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रथम चरण में 500 ई-टैक्सी के परमिट जारी करेगी तथा मांग के आधार पर निकट भविष्य में इनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विभागों में डीजल गाड़ियों को भी चरणबद्ध तरीके से कम किया जाएगा तथा ई-टैक्सी को बढ़ावा दिया जाएगा।

बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. अभिषेक जैन, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया, ओएसडी गोपाल शर्मा सहित सहकारी, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

लोक निर्माण मंत्री ने मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र में किए 50 करोड़ के उद्घाटन शिलान्यास

शिमला/शैल। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में सड़कों के सुधार और विस्तार पर 2600 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। यह धनराशि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत प्रदेश में मौजूदा सड़क नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण तथा उनके नई तकनीक के साथ रखरखाव पर खर्च की जाएगी।

उन्होंने यह बात मंडी के सदर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 50 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए कही। इस अवसर पर सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी उपस्थित रहीं।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार प्रदेश में सड़कों के गुणात्मक सुधार को लेकर काम कर रही है। मौजूदा सड़क नेटवर्क की मजबूती, उन्हें चौड़ा करने, विस्तार देने तथा नई तकनीक से रखरखाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

लोक निर्माण मंत्री तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने मंडी सदर विधानसभा में लगभग 50 करोड़ रुपये के उद्घाटन और शिलान्यास किए। उन्होंने मंडी शहर के समीप गणपति नाला पर विधायक प्राथमिकता में बने 2.80 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पुल का उद्घाटन किया। इस मौके मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा भी उपस्थित रहे।

लोक निर्माण मंत्री तथा सांसद ने प्रधानमंत्री ग्रामसड़क योजना फेस-3 के तहत 21.71 करोड़ रुपये की लागत से स्तरोन्नयन होने वाले गणपति सड़क के भूमि पूजन तथा 5 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले खलियाणा-मटयारी सड़क का शिलान्यास और कसाण-रछोड़ा सड़क का उद्घाटन किया। उन्होंने बस स्टैंड कोटली से कोटली-नैनादेवी बस सेवा का शुभारंभ भी किया।

उन्होंने 2 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई भरगांव से अलग वाया टिल्ला सड़क का उदघाटन, 8.51 करोड़ रुपये की लागत से बनने अणा कैंची से कुसमल सड़क का भूमि पूजन तथा 4.86 करोड़ रुपये से बनने वाली धार सुराड़ी से छतरेहड़ सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इन कार्यों को समयबद्ध पूरा करने का निर्देश दिया।

लोक निर्माण मंत्री ने खड्ड-कल्याणा, कसाणा और भरगांव में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि विकास कार्यों को गति देना उनकी प्राथमिकता है। संसाधनों की कमी के बावजूद विकास कार्यों को रूकने नही दिया जाएगा।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा मंडी जिले के जनहित के सभी विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा किया जाएगा।

विक्रमादित्य ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को स्वरोजगार में मदद के लिए पूर्ण संकल्पित है। सरकार ने इसी मकसद से 680 करोड़ रुपये का राजीव गांधी स्टार्ट अप योजना को मंजूरी दी है। इसमें ई टैक्सी खरीद पर 50 फीसदी सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि जिन ठेकेदारों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण एक और दो में कार्य पूरा नहीं किया। उन्हें तीसरे चरण में किसी भी सड़क निर्माण का ठेका नहीं दिया जाएगा।

इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार जनहित सर्वोपरि रखकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बार बार आग्रह पर भी आपदा में केन्द्र सरकार ने कोई भी राहत पैकेज नहीं दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपये देने का वायदा जल्द पूरा किया जाएगा। अगर प्रदेश में आपदा न आयी होती तो इस योजना को प्रदेश सरकार अब तक शुरू कर देती।

राज्य के प्रत्येक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्थापित की जाएगी लाइब्रेरी:संजय रत्न

शिमला/शैल। शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग और गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य के 762 स्कूलों में आवश्यक हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा मिल सके। यह उद्गार विधायक संजय रत्न ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घलौर के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्यातिथि अपने संबोधन में व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लाइब्रेरी रूमस स्थापित किए जाएंगे इसके साथ ही दस हजार मेधावी छात्रों को टेबलेट्स दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य ध्येय वर्तमान शैक्षणिक संस्थानों के आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना है जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। उन्होंने छात्रों से विद्यार्थी जीवन का आनन्द लेने के साथ-साथ जीवन में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परिश्रम करने का आहवान भी किया। विधायक संजय रत्न ने घल्लौर स्कूल के ग्राउंड बनाने के लिए 15 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने इस अवसर पर शैक्षणिक व अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया।

विद्यालय के ममता भाटिया ने मुख्यातिथि का स्वागत किया और स्कूल की वार्षिक गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। ..

जिसके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं, वह कभी भी अकेला नहीं रह सकता।

..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

ई.वी.एम.पर उठते सवाल घातक होंगे

ई.वी.एम. पर इन चुनावों के बाद भी सवाल उठने शुरू हो गये हैं। संभव है कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुंच जाये। क्योंकि सैंकड़ों साक्ष्य जुटा लिये जाने का दावा किया गया है। ई.वी.एम. पर हर चुनाव के बाद सवाल उठते आ रहे हैं। सभी राजनीतिक दल ई.वी.एम. की विश्वसनीयता पर सवाल उठा चुके हैं। ई.वी. एम. से 2004 से चुनाव करवाये जा रहे हैं और 2009 के चुनावों से ही इस पर सवाल उठने शुरू हो गये थे। वर्ष 2009 में पूर्व उप प्रधानमंत्री वरिष्ठतम भाजपा नेता एल.के.आडवाणी ने इस पर सवाल उठाये थे। वर्ष 2010 में तो भाजपा नेता जी.वी.एल. नरसिम्हा राव ने तो इस पर ''डेमोक्रेसी एट रिस्क-कैन वी ट्रस्ट ऑवर ई.वी.एम. मशीन लिख डाली थी। आडवाणी ने इस किताब की भूमिका लिखी है और नितिन गडकरी ने इसका विमोचन किया है। भाजपा नेता पूर्व मंत्री डॉ. स्वामी तो इस पर सुप्रीम कोर्ट भी गये थे और तब इसमें वी.वी.पैट का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2016 से 2018 के बीच उन्नीस लाख मशीने गायब हो चुकी है और आर. टी. आई. में यह जानकारी सामने आयी है। निर्वाचन आयोग ने इस तथ्य को स्वीकारा है। इन गायब हुई उन्नीस लाख ई.वी.एम. मशीनों के बारे में आज तक सरकार कुछ नहीं कर पायी है। हर चुनाव में ई.वी.एम. मशीनों को लेकर सैंकड़ों शिकायतें आती है। ई.वी.एम हैक होने से लेकर मशीन बदल दिये जाने के आरोप लगते है। दिल्ली विधानसभा में आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने तो ई.वी.एम. हैक करके दिखा दी थी। वर्ष 2017 में आप विधायक ने सदन के पटल पर यह प्रदर्शन किया था। इस तरह वर्ष 2009 से लगातार ई.वी.एम. के माध्यम से चुनाव करवाये जाने की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठते आ रहे है। मांग की जा रही है कि ई.वी.एम. के स्थान पर मत पत्रों से ही चुनाव करवाये जाये। लेकिन चुनाव आयोग पर इन सवालों और इस मांग का कोई असर नहीं हो रहा है। उन्नीस लाख ई.वी.एम. मशीनों के गायब होने पर जो आयोग और सरकार अब तक चुप बैठी है क्या उस पर आसानी से विश्वास किया जा सकता है। इस बार इन ई.वी.एम. मशीनों पर राजनेताओं और राजनीतिक दलों में नहीं वरन आम आदमी ने सवाल उठाये हैं। वरिष्ठ वकील इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इस समय ई.वी.एम. पर से आम आदमी का भरोसा लगातार टूटता जा रहा है। फिर ई.वी.एम. मशीन की सामान्य समझ के लिए भी इंजीनियर होना आवश्यक है। और इसका सीधा सा अर्थ है कि यह ई.वी.एम. मशीनों की वर्किंग आम आदमी की समझ से परे है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक जिस चयन प्रक्रिया की आम आदमी को बुनियादी समझ ही नहीं है उस पर विश्वास कैसे कर पायेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं ऐसे लोकप्रिय नेता के नेतृत्व में चुनाव चाहे जिस मर्जी प्रक्रिया से करवाये जाये उनकी पार्टी का जीतना तय है। इसलिये जिस प्रक्रिया पर आम आदमी का विश्वास हो और उसे समझ आती हो उसके माध्यम से चुनाव करवाने में नुकसान ही क्या है। यदि मत पत्रों से चुनाव करवाने और उनकी गणना करने में चार दिन का समय ज्यादा भी लग जाता है तो उसमें आपत्ति ही क्या है? यह समय लगने से नेता और चुनाव प्रक्रिया दोनों पर ही विश्वास बहाल हो जायेगा। इस समय उन्नीस लाख ई.वी.एम. मशीनों के गायब होने पर सरकार और चुनाव आयोग दोनों की निष्क्रियता आम आदमी की समझ में आने लगी है। इसमें आम आदमी का वर्तमान चुनाव प्रक्रिया पर से विश्वास उठना स्वभाविक है। यदि समय रहते इस प्रक्रिया को न बदला गया तो आम आदमी का आक्रोष क्या रूख अपना लेगा इसका अन्दाजा लगाना कठिन है।

समय की मांग है पैतृक संपत्ति में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण

गौतम चौधरी

पैतृक संपत्ति में अधिकार का कानून, जिसे आप विरासत कानून भी कह सकते हैं, किसी भी देश के कानूनी ढांचे का महत्वपूर्ण अंग है। यह परिवारों के भीतर संपत्ति और धन के न्यायोचित वितरण को सुनिश्चित करता है। भारत में, कई अन्य देशों की तरह, ये कानून सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परंपराओं में गहराई से जुड़े हुए हैं। इसके कारण कई प्रकार की विसंगति सामने आती रहती है। हालांकि हिन्दू कानून में कई प्रकार का बदलाव कर इसे समयानुकूल न्यायसंगत व व्यावहारिक बना दिया गया है लेकिन मुस्लिम समाज में ऐसा नहीं किया जा सका है। इसके पीछे महजबी सोच और पारंपरिक मान्यता लगातार प्रगतिशील परिवर्तन में अड़ंगा डालता रहा है। हमारे संवैधानिक सिद्धांतों के लिए यह लगातार चुनौती उत्पन्न कर रहा है। ऐसे में महिलाओं की विरासत से संबंधित इस्लामी कानूनों के बेहतर कार्यान्वयन की आवश्यकता के बारे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) द्वारा हाल ही में दी गयी स्वीकारोक्ति को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। एआईएमपीएलबी के द्वारा व्यक्त विचार समयानुकूल और प्रगतिशील सोच का द्योतक है। एआईएमपीएलबी के हाल की मान्यता अधिक मानकीकृत और न्यायसंगत दृष्टिकोण पर आधारित प्रतीत होता है। महिलाओं की विरासत से संबंधित इस्लामी कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन में एआईएमपीएलबी द्वारा कमियों को पहचानना एक स्वागत योग्य कदम है। यह विरासत अधिकारों के संदर्भ में लैंगिक असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता की बढ़ती स्वीकार्यता का प्रतीक है। इस्लामी कानून, किसी भी अन्य धार्मिक कानून की तरह, समाज के साथ विकसित होने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे निष्पक्ष और न्यायसंगत हों, खासकर उन महिलाओं के लिए जिन्होंने विरासत के मामलों में ऐतिहासिक रूप से असमानता का सामना किया है।

भारत की कानूनी प्रणाली, धर्म पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों का एक जटिल जाल प्रस्तुत करती है, जिसके परिणामस्वरूप अकसर महिलाओं के लिए असमान विरासत अधिकार सामने आते हैं। यहां बता दें कि भारत चूंकि एक धर्मनिर्पेक्ष देश है इसलिए यहां हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और अन्य समुदायों के अपने-अपने पारंपरिक कानून हैं, जिससे विभिन्न प्रथाएं संचालित होती है और उसकी व्याख्या भी अपने-अपने तरीके से भिन्न है। यह एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जहां महिलाओं को, उनकी धार्मिक संबद्धता के आधार पर, विरासत के मामलों में असमान व्यवहार का सामना करना पड़ता है। इससे उनके आर्थिक सशक्तिकरण और समग्र प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है।

धार्मिक समुदायों में विरासत कानूनों को संहिताबद्ध करने की प्रक्रिया विरासत के सिद्धांतों को मानकीकृत करेगी, जिससे सभी व्यक्तियों के लिए उनकी आस्था की परवाह किए बिना, समान व्यवहार सुनिश्चित किया जा सकेगा। समानता, न्याय और गैर-भेदभाव के संवैधानिक लोकाचार का पालन करते हुए, संहिताकरण, विविध कानूनों को एक व्यापक कानूनी ढांचे में सुसंगत और सुव्यवस्थित किया जा सकता है। कई देशों में इस प्रकार की संहिता है भी। ऐसा कदम न केवल महिलाओं के विरासत अधिकारों को मजबूत करेगा, बल्कि कानूनी प्रक्रियाओं को भी सरल बनाएगा, जिससे वे सामान्य आबादी के लिए अधिक सुलभ हो सकेगा। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को समानता और गैर-भेदभाव के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। विरासत कानूनों का संहिताकरण इन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होगा। एक समान दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा और लिंग, धर्म या जाति के आधार पर भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करेगा। यह इस सिद्धांत को सुदृढ़ करेगा कि प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान है और समान सुरक्षा व लाभ का हकदार है। इस पहल के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए विरासत कानूनों को संहिताबद्ध करने के प्रयासों के साथ-साथ व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। आवश्यक कानूनी सुधारों के लिए समर्थन जुटाने और आम सहमति बनाने के लिए धार्मिक नेताओं, कानूनी विशेषज्ञों, आम नागरिकों, समाज संगठनों और नागरिकों सहित विभिन्न हितधारकों को शामिल करना महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए सरकार को भी अपने तरीके से अभियान चलाने चाहिए।

महिलाओं की विरासत से संबंधित इस्लामी कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता को एआईएमपीएलबी की मान्यता समान नागरिक संहिता के तहत प्रस्तावित समान कानूनों के अनुरूप प्रतीत होता है। एआईएमपीएलबी के प्रयासों को धार्मिक सीमाओं से परे भारत में विरासत कानूनों को संहिताबद्ध करके एक व्यावहारिक कदम में तब्दील किया जाना चाहिए, जो यूसीसी के तहत आसानी से संभव हो सके। यह एकरूपता तो प्रदान करेगा ही साथ ही समानता और न्याय को सुनिश्चित करने की कोशिश भी करेगा। विरासत कानूनों को संवैधानिक ढांचे के साथ सरेखित करेगा और सभी के लिए समानता के सिद्धांत को कायम करेगा। इस परिवर्तन को आगे बढ़ाने, अंततः एक अधिक समावेशी और प्रगतिशील समाज को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक भागीदारी को सूनिश्चत करना बेहद जरूरी है।

वर्ल्ड फूड इंडिया 2023

हिमाचल प्रदेश का काला लहसुन, कच्छ का ड्रैगन फ्रूट या कमलम, मध्य प्रदेश का सोया मिल्क पाउडर, लद्दाख का करकिचू सेब, पंजाब का कैवेंडिश केला, जम्मू का गुच्ची मशरूम सहित कई उत्पाद हैं जो पहली बार विदेशी बाजार में जा रहे हैं, उनकी पहली पसंद बन गए हैं।

भारत की भोजन विविधता दुनिया के निवेशकों के लिए लाभांश

भोजन प्रत्येक मनुष्य की दिनचर्या का अभिन्न अंग है। अच्छे व्यंजन अजनबियों में भी एक बंधन स्थापित करने में मदद करते हैं। भारत में शाही पाक विरासत और व्यंजनों की एक परंपरा रही है।

व्यापार करने में सुगमता की नीति और राजकोषीय प्रोत्साहन भारतीय खाद्य अर्थव्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय रुचि पैदा कर रहे हैं। भारत से सालाना 13 अरब डॉलर से अधिक का प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात होता है। उसी समृद्ध भारतीय खाद्य संस्कृति से विश्व को परिचित कराने का बड़ा माध्यम बन रहा है वर्ल्ड फूड इंडिया जिसके तीन दिवसीय दूसरे संस्करण का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नवंबर को किया उद्घाटन आज भारत में एग्री इंफ्रा फंड के तहत पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हजारों प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। इसमें 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश हुआ है। आज भारत में निवेशक – अनुकूल नीतियां बनी हैं, वो खाद्य क्षेत्र को एक नई ऊंचाई पर ले जा रही है। खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हर क्षेत्र में भारत ने अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की है। ये हर कंपनी और स्टार्टअप के लिए सुनहरा अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के उद्घाटन पर ये शब्द यूं ही नहीं कहे। उसके पीछे भारत की 140 करोड़ की जनशक्ति, कई कृषि वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक होना, भारत की रणनीतिक, भौगोलिक स्थिति, विशाल कार्यबल और अनुकूल कारोबारी माहौल भी इसे वैश्विक खाद्य व्यवस्था के लिए एक आशाजनक केंद्र बनाते हैं।

भारत में कहा जाता है, 'यथा अन्नम्, तथा मन्नम्'। अर्थात् हम जैसा खाना खाते हैं, वैसा ही हमारा मन भी बनता है। यानी, खाना न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत बड़ा कारक होता है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। भारत की टिकाऊ खाद्य संस्कृति हजारों वर्षों की विकास यात्रा का परिणाम है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन के बाद स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए एक लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह सदस्यों को 380 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी सहायता वितरित की।

इस प्रारंभिक पूंजी से स्वयं सहायता समूह को बेहतर पैकेजिंग और गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण के माध्यम से बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने फूड स्ट्रीट का भी उद्घाटन किया। वहीं वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के समापन सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि हमें उन खाद्य पदार्थों की ओर जाना चाहिए जो न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए बल्कि पृथ्वी और प्रकृति को भी किसी तरह का नुकसान न पहुंचाए।

वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित 80 से अधिक देशों के प्रतिभागी शामिल हुए। नीदरलैंड आयोजन में भागीदार देश और जापान फोकस देश रहा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को – दुनिया के खाद्य केंद्र के रूप में प्रदर्शित करना और 2023 को अंतरराष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष के रूप में मनाना रहा। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 भारतीय खाद्य अर्थव्यवस्था का प्रवेशद्वार है, जो भारतीय और विदेशी निवेशकों के बीच साझेदारी की सुविधा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को सनराइज क्षेत्र बताया है।

पीएम मोदी कहते हैं कि दुनिया के लिए टिकाऊ और खाद्य सुरक्षित भविष्य की नींव पड़ेगी। टिकाऊ जीवन यापन के लिए खाद्य पदार्थों की बर्बादी को भी रोकना एक बड़ी चुनौती है। हमारे उत्पाद ऐसे होने चाहिए जिनसे बर्बादी रुके। भारत ने जी – 20 की अध्यक्षता के दौरान नई दिल्ली में नेताओं की घोषणाओं में भी टिकाऊ कृषि, खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा पर जोर दिया है। वर्तमान सरकार के दौरान ही भारत ने पहली बार एग्री एक्सपोर्ट नीति बनाई। देशभर में लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क खड़ा किया। आज भारत में 100 से ज्यादा जिला स्तर पर निर्यात हब तैयार हैं जिससे जिले सीधे दुनियाभर के बाजार से जुड़ रहे हैं।

भारत में जितनी सांस्कृतिक विविधता है, उतनी ही खाद्य विविधता, भोजन विविधता भी है। हमारी ये भोजन विविधता, दुनिया के हर निवेशक के लिए एक लाभांश है। आज जिस तरह पूरी दुनिया में भारत के प्रति जिज्ञासा बढ़ी है वो भी बहुत बड़ा अवसर है। पूरी दुनिया खाद्य उद्योग के पास, भारत की खाद्य परंपराओं से भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। – नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विकास के तीन आधार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भारत की विकास गाथा के तीन प्रमुख आधार बताए हैं। छोटे किसान, छोटे उद्योग और महिलाएं। छोटे किसानों की भागीदारी और उनका लाभ बढ़ाने के लिए 10 हजार एफपीओ बनाए जाने हैं जिसमें 7 हजार बन चुके हैं। लघु उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण में करीब 2 लाख अति लघु उद्योगों को संगठित किया जा रहा है। वहीं भारत दुनिया को महिलाओं के नेतृत्व में विकास का मार्ग दिखा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है जिसका फायदा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को हो रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भारत

- 50,000 मिलियन डॉलर से ज्यादा का एग्रो एक्सपोर्ट कर भारत आज दुनिया में 7वें नंबर पर आ गया है।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र ने वर्ष 2014 – 15 से अब तक 6 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आकर्षित किया।
- वर्ष 2014 – 15 में प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात 4.96 अरब डॉलर था जो 2022 – 23 में बढ़कर 13.07 अरब डॉलर का हो गया।
- कृषि खाद्य उत्पाद में प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात की भागीदारी 2014 – 15 में 13.7% थी जो 2022 – 23 में बढ़कर 25.60% हो गई है।
- देश की प्रसंस्करण क्षमता 12 लाख मीट्रिक टन थी जो अब दो करोड़ मीट्रिक टन से भी ज्यादा है। यानी 9 वर्षों में 15 गुना से ज्यादा की वृद्धि।
- नई खाद्य इकाइयों के लाभ पर आयकर में 100% छूट दी जाती है। पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र के कुल कार्यबल में 12.2% कर्मचारी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत हैं।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की पिछले 5 वर्षों में 9% की औसत विकास दर रही है।
- देश में 23 मेगा फूड पार्क और 12 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर ऑपरेशनल हैं।
- देश में 271 एकीकृत कोल्ड चेन और 140 परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं।

स्थायी पर्यटन के विकास के लिये गंतव्य आधारित क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू

शिमला। पर्यटन मंत्रालय ने गंतव्य आधारित क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यटन स्थलों और गंतव्य स्थानों के पास रहने वाले स्थानीय लोगों व सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करना, विकास करना, संवेदनशील बनाना और सेवाओं/प्रशिक्षणों को उन लोगों के घरों तक पहुंचाना है, जो प्रशिक्षण लेने के लिए शहरों/कस्बों की यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं।

अब तक इस पहल के तहत 12,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और पूरे देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर 150 से अधिक ऐसे प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं। पर्यटन मंत्रालय ने भारत को स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन के लिए एक पसंदीदा वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से टिकाऊ पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति तैयार की है।

स्थायी पर्यटन के विकास के लिए निम्नलिखित रणनीतिक स्तंभों को चिह्नित किया गया है।

1. पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना
2. जैव विविधता की रक्षा करना
3. आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना
4. सामाजिक – सांस्कृतिक स्थिरता को बढ़ावा देना
5. स्थायी पर्यटन के प्रमाणीकरण पर योजना
6. आईईसी और क्षमता निर्माण
7. शासन

स्थायी पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए मंत्रालय ने भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) को केंद्रीय नोडल एजेंसी – स्थायी पर्यटन (सीएनए – एसटी) के रूप में नामित किया है।

आतिथ्य सत्कार सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय मेलों/त्यौहारों और पर्यटन से संबंधित कार्यक्रमों (यानी सेमिनार, सम्मेलन, अभिसमय आदि) के प्रस्ताव पर राज्य सरकारों को 50 लाख रुपये तक और केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन को 30 लाख रुपये तक की केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।

इस योजना में निम्नलिखित घटक शामिल हैं –

i) अर्द्ध – स्थायी संरचनाओं का निर्माण

ii) पोस्टर, पैम्फलेट, समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन और फिल्म का निर्माण

iii) कलाकारों का पारिश्रमिक

iv) बैठने की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, ध्वनि, आवास व बोर्डिंग, परिवहन, स्थान किराए पर लेना और इसी तरह की अन्य गतिविधियां

इस योजना दिशानिर्देशों में पर्यटकों को स्थानीय पर्व और सांस्कृतिक मेलों को देखने के लिए विशेष व्यवस्था और सुरक्षा प्रदान करने का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। हालांकि, राज्य सरकारें अपने – अपने अधिकार क्षेत्र में पर्यटकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती हैं।

पर्यटन मंत्रालय (एमओटी) देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और सुविधाएं प्रदान करने के लिए 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्द्धन अभियान' यानी प्रसाद और 'केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' योजनाओं के तहत राज्य सरकारों/ केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन/केंद्रीय एजेंसियों को विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पर्यटन मंत्रालय राज्य पर्यटन विभागों को पर्यटक सूचना और सुविधा में सुधार के साथ – साथ अपने पर्यटक उत्पादों के विपणन व प्रचार – प्रसार को लेकर प्रमुख आईटी पहल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके तहत मंत्रालय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे वे अपने पर्यटन उत्पादों व सेवाओं में प्रचार – प्रसार, विपणन आदि सहित सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग को अपना सकें। इस योजना के तहत आईटी परियोजना (राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की) की लागत का 50 फीसदी हिस्सा वित्तीय सहायता के रूप में राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों को दी जाती है, जो हर एक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के लिए एक वार्षिक सीमा निर्धारित की गई है, जो कुल परियोजना लागत का 90 फीसदी या 50 लाख रुपये (जो भी कम हो) होगा।

यह जानकारी लोकसभा में केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री जी.किशन रेड्डी ने दी।

आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड्स में हिमाचल को दो पुरस्कार

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश ने नई दिल्ली में आयोजित आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड्स-2023 समारोह में दो प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते। इस

समारोह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्यातिथि उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश ने कांगड़ा जिले के बीड़-बिलिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटक गंतव्य स्वर्ण श्रेणी और लाहौल-स्पीति जिले के स्पीति के लिए सर्वश्रेष्ठ इको-पर्यटन गंतव्य स्वर्ण श्रेणी में पुरस्कार जीते। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आर.एस. बाली ने यह पुरस्कार प्राप्त किए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निवेशकों से हिमाचल में पर्यटन क्षेत्र में उदारतापूर्वक निवेश करने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल धार्मिक पर्यटन का मुख्य केंद्र है, प्रदेश प्रसिद्ध शक्तिपीठों की भूमि है और शीघ्र ही प्रदेश आध्यात्मिक पर्यटन का मुख्य केंद्र बन कर उभरेगा। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में ईको-टूरिज्म को भी बड़े पैमाने पर विकसित करने पर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मार्च, 2026 तक हिमाचल को देश के हरित राज्य के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है।

आउटलुक ट्रैवलर की प्रकाशक मीनाक्षी मेहता ने मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों का स्वागत किया।

इस अवसर पर आउटलुक ग्रुप के सीईओ इंद्रनील राय ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

इस अवसर पर गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खौंटे, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, मुख्यमंत्री के ओएसडी केएस बांशटू, पत्रिका की संपादक आनंदिता घोष और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

आउटलुक बिजनेस मैगजीन के 'चेंजमेकर्स आफ द ईयर-2023' बने सुक्खू

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आउटलुक बिजनेस पत्रिका की प्रतिष्ठित 'चेंजमेकर्स आफ द ईयर-2023' की सूची में स्थान अर्जित किया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान मुख्यमंत्री को उनके असाधारण नेतृत्व और उल्लेखनीय योगदान विशेषकर इस वर्ष मानसून के दौरान भीषण आपदा को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संकट से निपटने का सराहनीय योगदान उन्हें इस विशिष्ट सूची में शामिल होने वाले देश के एकमात्र मुख्यमंत्री के रूप में दर्शाता है। यह सम्मान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, विराट कोहली और नीरज चोपड़ा जैसी प्रभावशाली हस्तियों के समान सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में उनके प्रभावशाली योगदान को रेखांकित करता है।

सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर योगदान की अपील:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सेना में हिमाचल प्रदेश के युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है तथा छोटे से इस राज्य के लिए यह गर्व का विषय है कि प्रदेश के वीर योद्धाओं ने देश की सीमाओं की बहादुरी से रक्षा करते हुए चार परमवीर चक्र प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा कि जब भी देश पर बाहरी आक्रमण हुए हमारे बहादुर सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने में कभी पीछे नहीं रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश पर बलिदान होने वाले इन जवानों के परिवारों की उचित सहायता करना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि युद्ध पीड़ितों तथा भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास एवं कल्याण के लिए राज्य सरकार निरन्तर प्रयासरत है तथा जनता का सहयोग भी इस अहम कार्य में अपेक्षित है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के अवसर वे बढ़-चढ़कर व उदारतापूर्वक से अपना योगदान दें ताकि इस धनराशि से सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की अधिक से अधिक मदद की जा सके।

डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का 12वां दीक्षांत समारोह आयोजित

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सोलन जिले के नौणी स्थित डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर

सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्यातिथि शामिल हुए।

राज्यपाल ने 773 विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किये। इसके अलावा 1305 विद्यार्थियों को बी.एस.सी. औद्यानिकी और बी.एससी. वानिकी, बी.टेक बायो-टेक्नोलॉजी, एम.बी.ए./ए.बी.एम., एम.एससी. और पीएच.डी. औद्यानिकी एवं वानिकी में डिग्रियां प्रदान कीं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेधावी विद्यार्थियों को 23 स्वर्ण पदक प्रदान किये, जिनमें से 20 स्वर्ण पदक छात्राओं को प्रदान किये गये।

राज्यपाल ने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक नंद लाल शर्मा और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप-महानिदेशक शिक्षा राकेश चंद अग्रवाल को मानद उपाधि भी प्रदान की।

स्वर्ण पदक विजेताओं और डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने उनसे राष्ट्र निर्माण में योगदान का आहवान किया। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि छात्राओं को सर्वाधिक डिग्रियां एवं स्वर्ण पदक मिले हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने शोध कार्य को खेतों तक ले जाएं ताकि किसान इससे लाभान्वित हो सकें। वैज्ञानिकों द्वारा किया गया शोध प्रयोगशालाओं और किताबों से निकलकर व्यवहारिक रूप से खेतों तक पहुंचना आवश्यक है। युवा वैज्ञानिकों का कर्त्तव्य है कि वे किसानों की समस्याओं का उनके खेतों में जाकर समय पर इसका समाधान सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि युवा ही समाज में बदलाव ला सकते हैं। डिग्री प्राप्त करने का अर्थ केवल रोजगार अर्जित करना नहीं बल्कि समाज कल्याण की दिशा में इसका उपयोग करना है। उन्होंने कहा कि डिग्रीधारकों को 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की दिशा में कार्य करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर मेधावी छात्रों को बधाई दी और प्रत्येक स्वर्ण पदक विजेता को 10,000 रुपये की सम्मान राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और 23 स्वर्ण पदक विजेताओं में से 20 लड़कियां हैं। राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और कई जिलों में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पुलिस भर्ती में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। समाज के विकास में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रदेश सरकार लड़कियों की विवाह योग्य आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने पर विचार कर रही है और इस विषय पर परामर्श के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने 1.16 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित कौशल विकास छात्रावास और 40 लाख रुपये की लागत से निर्मित विवेकानंद योगा और मेडीटेशन सेंटर का लोकार्पण किया।

डॉ.यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राजेश्वर चंदेल ने विश्वविद्यालय की विभिन्न उपलब्धियों और अन्य गतिविधियों से अवगत करवाया। उन्होंने प्राकृतिक खेती और विकास में अनुसंधान के लिए चार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 2.50 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं और यह राशि 41 परियोजनाओं के माध्यम से विभिन्न विभागों को आवंटित की जाएगी।

इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक विनोद सुल्तानपुरी, विश्वविद्यालय सीनेट, प्रबंधन बोर्ड और अकादमिक परिषद के सदस्य, विश्वविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

प्रदेशभर में 40 शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर स्थापित करेगी सरकार

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए, सरकार प्रदेशभर में 40 शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर स्थापित करने पर विचार कर रही है। यह केंद्र राज्य के लोगों को घर-द्वार के समीप आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने में नई आशा की किरण साबित होंगे। प्रत्येक शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर में एक समर्पित स्वास्थ्य टीम होगी, जिसमें एक चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट, सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का विस्तार और सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, मरीजों की संख्या और मृत्यु दर कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे दूसरे और तीसरे स्तर के ईलाज की आवश्यकता कम होती है, जिससे उपचार पर होने वाला खर्च भी कम होता है।

वर्तमान में, एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 50,000 व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। इस दूरदर्शी और महत्त्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य प्रत्येक शहरी स्वास्थ्य वेलनेस केन्द्र द्वारा लगभग 20,000 लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है ताकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। इन शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना एक मजबूत और समावेशी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

यह नवीन प्रयास शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों और आजीविका के लिए अन्य राज्यों से आए लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह महत्त्वाकांक्षी योजना सर्वजन तक बेहतर स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करवाने में मील पत्थर साबित होगी, जिसके माध्यम से शहरों में स्वास्थ्य क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का समाधान सुनिश्चित हो सकेगा।

नौणी विवि एवं अनुसंधान केन्द्रों पर वार्षिक शीतोष्ण फलदार पौधों की बिक्री शुरू

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी और विवि के कृषि विज्ञान केंद्रों और अनुसंधान स्टेशनों में बागवानों के लिए फलदार पौधे की वार्षिक बिक्री सोमवार से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर शुरू हो गई। फल रोपण सामग्री की वार्षिक बिक्री के लिए हिमाचल प्रदेश और आसपास के राज्यों के किसान विश्वविद्यालय और क्षेत्रीय केन्द्रों पर एकत्र हुए।

इस बिक्री के दौरान किसानों द्वारा सेब, नाशपाती, खुमानी, आड़ू, नेक्टराइन, चेरी, कीवीफ्रूट, अखरोट, अनार, प्लम, जापानी फल और बादाम आदि की विभिन्न किस्मों को खरीदा गया। हिमाचल और आसपास के राज्यों के विभिन्न हिस्सों से किसान विभिन्न किस्मों के फलों के पौधे खरीदने के लिए विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्रों पर आये। बिक्री के पहले दिन 782 किसानों ने नौणी में विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में तीन नर्सरियों, कंडाघाट, रोहड़ू में कृषि विज्ञान केंद्र और मशोबरा, बजौरा और शारबो (किन्नौर) में अनुसंधान केंद्रों से विभिन्न फलों की किस्मों के 22,324 से अधिक पौधे खरीदे।

इस वर्ष, किसानों ने फलों की फसलों के विविधीकरण के प्रति रुचि दिखाई है और यह बिक्री के दौरान भी दिखाई दी, जहां सेब की विभिन्न किस्मों के साथ-साथ जापानी फल, अखरोट, कीवी और अन्य गुठलीदार फलों की मांग में वृद्धि देखी गई।

इस वर्ष, विश्वविद्यालय और क्षेत्रीय स्टेशनों पर बिक्री के लिए उपलब्ध पौधों की कुल संख्या 2.72 लाख से अधिक है। इस बिक्री के दौरान किसानों को सेब, कीवी, अनार, खुमानी, आड़ू, नेक्टराइन, चेरी, अखरोट, नाशपाती, प्लम आदि की विभिन्न किस्में उपलब्ध कारवाई जाएंगी। सेब के लगभग 50000 क्लोनल रूटस्टॉक भी उपलब्ध होंगे। आने वाले दिनों में यह बिक्री जारी रहेगी।

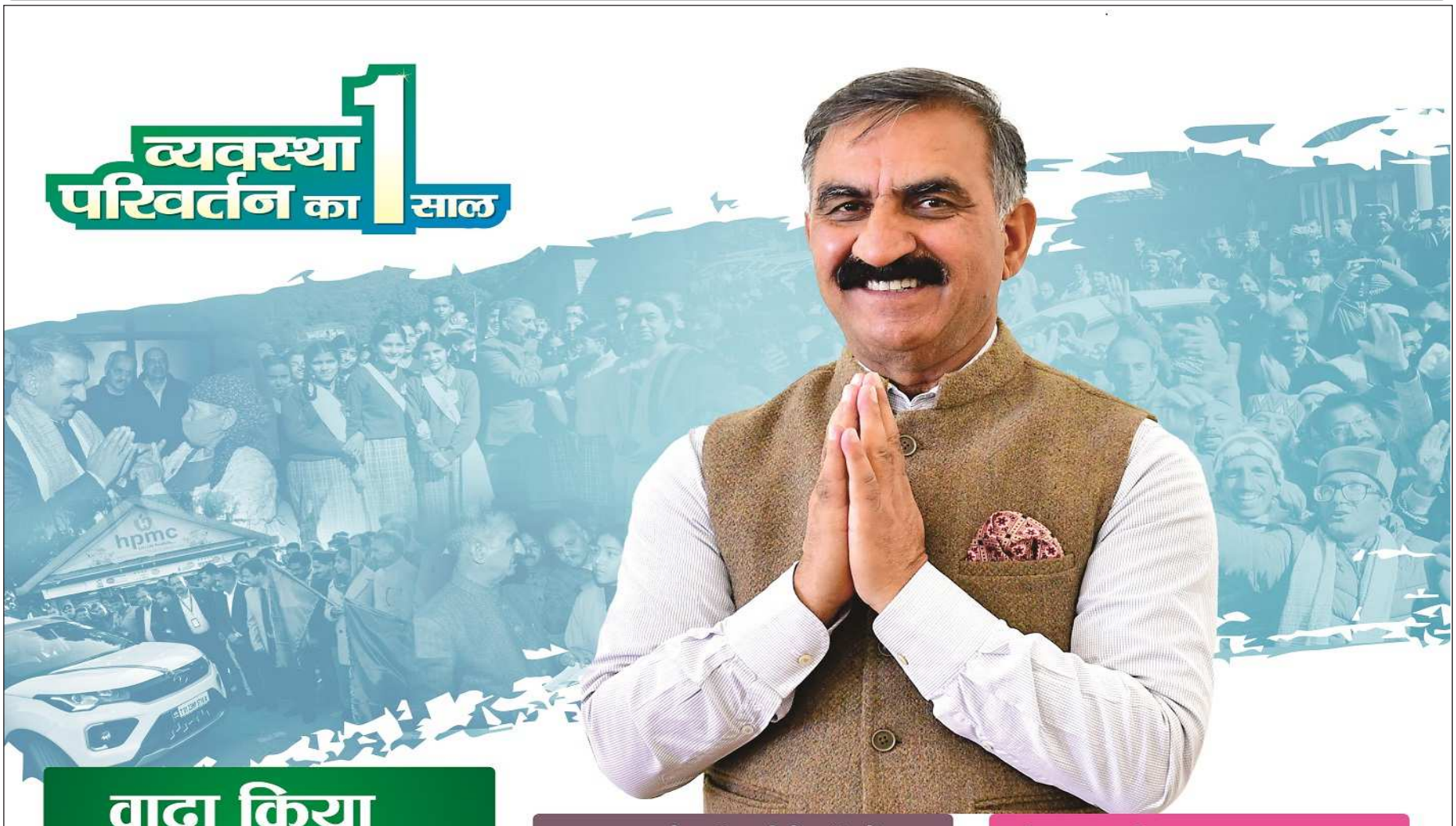

वादा किया वादा निभाया

अपनी चुनावी गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की बहाल

कर्मचारियों को मिली सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा और आत्मसम्मान

1.36 लाख NPS कर्मचारियों को मिली OPS की सौगात

युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोज़गार स्टार्ट-अप योजना आरम्भ कर चुनावी गारंटी की पूरी

युवाओं को ई-टैक्सी की खरीद पर 50% सब्सिडी

युवाओं को रोज़गार सुनिश्चित करने के लिए ई-टैक्सियों को सरकारी संस्थानों में लगाने का प्रावधान

आगामी शैक्षणिक सत्र से सभी सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम आरम्भ करने की चुनावी गारंटी पूरी

इंतकाल-राजस्व लोक अदालतों में 45055 इंतकाल मामलों का निपटारा

प्रदेश में पहली बार विशेष इंतकाल-राजस्व अदालतों का आयोजन कर आम जन को पहुंचाई राहत

युवा ऊर्जा का साथ हरित हिमाचल का होगा विकास

ई-वाहनों को प्रोत्साहन, प्रदूषणमुक्त हिमाचल

युवाओं को ई-वाहनों की खरीद पर 50% सब्सिडी

चार्जिंग स्टेशन के लिए 50% सब्सिडी

युवाओं को रोज़गार के अवसर अपार

राज्य सरकार शीघ्र भरेगी 18 हज़ार से अधिक पद

अध्यापक 5291, वन मित्र 2061, जल शक्ति विभाग में 10 हज़ार व पुलिस कर्मियों के 1226 पद (महिलाओं के लिए 30% आरक्षण)

भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस

नौकरियों में युवाओं के साथ हो रहे धोखे को देखते हुए कर्मचारी चयन आयोग किया भंग

नीतिगत सुधार करते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना

मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना

अनाथ बच्चों और बेसहारा वर्गों के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश

4000 अनाथ बच्चे बने 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट'

27 वर्ष तक के अनाथ बच्चों को 4000 मासिक पॉकेट मनी, कोचिंग के लिए ₹1लाख, लघु/सूक्ष्म उद्योग लगाने के लिए ₹2लाख, 2/3 बिस्वा भूमि और मकान निर्माण के लिए ₹3लाख और विवाह के लिए ₹2लाख अनुदान

गुणात्मक शिक्षा की दिशा में व्यापक सुधार

तकनीकी शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को 1% ब्याज पर ₹20 लाख तक ऋण

हर विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से लैस राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल, 18 स्कूल शीघ्र स्थापित किए जाएंगे

प्रदेश में 2050 उत्कृष्ट पाठशालाएं होंगी स्थापित

सभी सरकारी स्कूलों में प्रौद्योगिकी और डेटा-संचालित प्रणाली लागू करने का निर्णय

स्वास्थ्य सुविधाएं हुईं बेहतर

हर विधानसभा क्षेत्र में बनेगा एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान

सभी मेडिकल कॉलेजों में शीघ्र रोबोटिक सर्जरी

36 विधानसभा क्षेत्रों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टर नियुक्त

आरपीजी मेडिकल कॉलेज, टांडा में ओपन हार्ट सर्जरी शुरू

ऐतिहासिक फैसलों का प्रमाण समृद्ध होते किसान-बागवान

सेब और आम के फलों के समर्थन मूल्य में ₹1.50 की ऐतिहासिक वृद्धि, ₹10.50 से बढ़ाकर ₹12 प्रति किलो ग्राम

सेब की बिक्री किलो के हिसाब से करने का निर्णय

महिला सशक्तिकरण

मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए ₹1.50 लाख की सहायता

विधवा पुनर्विवाह योजना की सहायता राशि ₹65,000 से बढ़ाकर ₹2 लाख

इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के तहत एक बेटी के बाद परिवार नियोजन अपनाने पर प्रोत्साहन राशि ₹35000 से बढ़कर ₹2 लाख और 2 बेटियों के बाद ₹35000 से बढ़ाकर ₹1 लाख

लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन कर पैतृक सम्पत्ति में बेटियों को बेटों के समान अधिकार

निरन्तर प्रयासों से पर्यटन विकास

कांगड़ा जिला बनेगा पर्यटन राजधानी

हर ज़िले में स्थापित किया जा रहा हेलीपोर्ट

कांगड़ा जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चिड़ियाघर एवं गोल्फ कोर्स होगा स्थापित

ऐतिहासिक आपदा राहत पैकेज

राहत नियमावली में बदलाव कर मुआवज़े को बढ़ाया

प्रभावितों को ₹4500 करोड़ की राहत

पूर्ण क्षतिग्रस्त घरों के लिए ₹7 लाख

प्रभावितों को मुफ्त रसोई गैस व राशन

शहरी व ग्रामीण इलाकों में किराये पर मकान के लिए मदद (₹10000 व ₹5000)

व्यवस्था परिवर्तन के लिए ठोस कदम

कर्मचारियों के हित में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बहाल करने का फैसला

विकास कार्यों के शीघ्र निष्पादन के लिए लोक निर्माण व जल शक्ति विभागों की राज्य परियोजनाओं में टेंडर प्रक्रिया 51 दिनों से घटाकर 30 दिन की गई

वन विभाग के निर्माण कार्यों को विशेषज्ञ विभागों द्वारा करवाए जाने का निर्णय

राज्य में संचालित जल विद्युत परियोजनाओं में बिजली उपदान पर जल उपकर (Water Cess) लगाया गया

सरकारी भूमि की लीज़ अवधि 99 वर्ष से घटाकर 40 वर्ष की

सूचना एवं जन संपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार www.himachalpr.gov.in HimachalPradeshGovtIPRDept diprhimachal dprhp

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

नये वर्ष से मिलेगी महिलाओं को 1500 रूपये की पैन्शन

20,000 नौकरियां भी 31 मार्च से पहले देने का हुआ ऐलान
यह बड़े हुये खर्च कैसे पूरे किये जायेंगे इस पर लगी निगाहें

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 16 अप्रैल 2023 को हिमाचल दिवस के मौके पर लाहौल स्पीति की 9000 महिलाओं को 1500 रूपये की घोषित पैन्शन दिये जाने की घोषणा की थी। उस पर पहली जनवरी 2024 से अमल शुरू हो जायेगा। इसी के साथ प्रदेश की 2.37 लाख महिलाओं को जिन्हें इस समय 1100 रुपए पैन्शन के मिल रहे हैं उन्हें भी 1500 – 1500 रूपये की पैन्शन दी जायेगी और इस तरह हर महिला को 400 रूपये की अतिरिक्त आय हो जायेगी। प्रदेश में 20 हजार युवाओं को भी रोजगार देने का ऐलान किया गया है। 31 मार्च से पहले वनरक्षक, पंप ऑपरेटर, पुलिस आरक्षी, बहुउद्देशीय कामगार, जेबीटी, टीजीटी प्रवक्ताओं और पटवारीयों आदि की भी भर्ती की जायेगी। यह घोषणा भी धर्मशाला में की गयी है। 18 से 60 साल की विधवाओं के

बच्चों की उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई में सरकार मदद करेगी यह ऐलान भी सरकार कर चुकी है। अगले वर्ष से सोलर पावर योजना से युवाओं को लाभ देने का भरोसा दिया गया है। अगले वर्ष में ही मिल्क फैड 31 रूपये प्रति लीटर की जगह 37 रूपये प्रति लीटर दूध खरीदेगा। पहली वर्षगांठ के अवसर पर की गयी इन घोषणाओं को अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के दबाव के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि जो 10 गारंटीयां पिछले चुनावों में दी गयी थी और अब उनको चरणबद्ध तरीके से पांच वर्षो में पूरा करने की बात की जा रही है इसका जनता पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। बल्कि इसे सरकार की वादा खिलाफी करार देकर भाजपा ने अभी हुये पांच राज्यों के चुनावों में भी इसे प्रचारित किया है। इस परिदृश्य में यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार पूरी तरह चुनावी दबाव में आ गयी है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा की सरकार इन घोषणाओं को पूरा करने के लिये वित्तीय प्रबंध कैसे करती है। क्योंकि वर्ष 2023 – 24 का जो बजट पारित है उसके संसाधनों से यह हो पाना संभव नहीं है। क्योंकि वर्ष 2023 – 24 का बजट ही वर्ष 2022 – 23 के बजट से कुल आकार में कम है। इसलिए ऐसे अतिरिक्त बोझ के लिये सरकार के पास कर्ज लेने के लिए अतिरिक्त और कोई विकल्प ही नहीं रह जाता है। कर्ज लेने पर सरकार पर पहले से ही उंगलियां उठ रही हैं और कर्ज लेना सरकार को और विवादित बना देगा यह तय है। ऐसे में यह देखना रोचक होगा की इन घोषणाओं को पूरा करने के लिये सरकार क्या तरीका अपनाती है। कुछ वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ाकर आम आदमी की जेब से यह खर्च वसूला जाता है या अपने अवांछित खर्च कम करके। इस समय सरकार द्वारा की गई बहुत सारी ताजपोशियां आम आदमी की नजर में फिजूल खर्च है।

पहली ही सालगिरह पर केंद्रीय नेतृत्व का न आना भाजपा को दे गया मुद्दा

राहुल प्रियंका और खड़गे का न आना सरकार को डाल गया संकट में
जयराम ने इसे पूरी राजनीति से परोसा जनता में
क्या कांग्रेस नेतृत्व इसका जवाब दे पायेगा
उठने लगा है सवाल

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार की पहली ही सालगिरह पर राहुल और प्रियंका गांधी के न आने को नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जिस तरह से अपने विरोध प्रदर्शन पर जनता के सामने रखा है उससे प्रदेश के सियासी हल्कों में सारे समीकरण गड़बड़ा गये हैं। क्योंकि जयराम ने दावा किया है कि ''हमने पहले ही कह दिया था कि अगर उनमें थोड़ी भी शर्म होगी तो नहीं आयेंगे।'' सरकार की पहली ही सालगिरह पर इन केंद्रीय नेताओं का न आना अपने में ही बहुत कुछ कह जाता है। फिर जिस तरह से जयराम ने इस न आने को पेश किया है वह उसका सबसे बड़ा सियासी स्टोक माना जा रहा है। क्योंकि

हिमाचल सरकार की पहले साल की असफलताओं को ही भाजपा ने तीनों चुनावी राज्यों मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में खूब प्रचलित किया था और आज हिमाचल भाजपा इन राज्यों में कांग्रेस की असफलता को इस प्रचार का प्रतिफल मान रही है। जयराम के इस दावे से अनचाहे ही यह संकेत और संदेश चला गया है कि हिमाचल सरकार में सब अच्छा नहीं चल रहा है। जयराम के इस कथन से प्रदेश कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और प्रदेश का हर आदमी यह सोचने लग जायेगा कि क्या सही में कांग्रेस हाईकमान प्रदेश सरकार के कामकाज से प्रसन्न नहीं है।

अभी अभी कांग्रेस तीन राज्यों में चुनाव हारी और उस हार में हिमाचल सरकार कि परफॉरमैन्स को भी एक कारण माना गया है। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनावों में प्रदेश सरकार और संगठन का मनोबल गिराने के लिए राहुल – प्रियंका और खड़गे का न आना उस समय तो और भी गंभीर हो जाता है जब उनके आने का प्रचार किया जा रहा हो। भाजपा सरकार की गारंटीयों पर पहले से ही आक्रामक चल रही है। आरटीआई के माध्यम से प्रमाण जुटाकर जनता के सामने रख रही है। जबकि सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर भाजपा काल से चले आ रहे प्रशासन को ही अभी तक यथास्थिति रख कर चली आ रही है। हिमाचल कांग्रेस का कोई भी बड़ा छोटा नेता अभी तक भाजपा की नीतियों पर कोई सवाल तक नहीं कर पाया है। राहुल ने ही जिन मुद्दों पर प्रधानमंत्री और भाजपा को घेरा है उनको भी प्रदेश कांग्रेस के नेता आगे नहीं बढ़ा पाये हैं।

इस वस्तुस्थिति में सरकार के पहले ही समारोह में केंद्रीय नेतृत्व का न आ पाना प्रदेश की कांग्रेस को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जिसका कोई आसान जवाब दे पाना संभव नहीं होगा। जयराम द्वारा पैदा किये सन्देह का परिणाम दूरगामी होगा। इसका जवाब देने के लिये जो तथ्यात्मक आक्रामकता अपेक्षित है शायद उसके लिए सरकार, उसका तंत्र और सलाहकार कोई भी तैयार नहीं लगता। यह तय है कि जो बीज आज विपक्ष ने इस अनुपस्थिति पर बीज दिये हैं उनके फल भयंकर होंगे।